(ग) रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है और इन प्रयासों के परिणाम कब तक दिखाई पड़ेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० जी० वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) रेशम, आयातों की हमारी सूची में एक प्रतिबंधित मद है तथा इसका लाइसेंस के बिना आयात नहीं किया जा सकता है । सामान्यतः ऐसे लाइसेंस जारी नहीं किये जाते ।

इसके अलावा अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत निर्यातक अपने कच्चे माल की जरूरतों को पूरा करने के लिये चीन अथवा किसी भी अन्य देश से कच्चे रेशम का आयात करने के पात्र हैं ।

(ग) देश में रेशम का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान विस्तार तथा प्रशिक्षण एककों के अपने देश व्यापी नेटवर्क के जरिये आवश्यक सहायता प्रदान करके विभिन्न राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित कर रहा है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड किसानों को रेशम का उत्पादन शुरू करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये अनेक सहायता कार्यक्रम/योजनायें भी क्रियान्वित कर रहा है ।

Cotton production in Andhra Pradesh

2433. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the total quantity of cotton produced in Andhra Pradesh;

(b) what is the quantity of it is purchased by Cotton Corporation of India; and

(c) what is the share of Andhra Pradesh in the total production and the total purchase of cotton by CCI in the country?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMI): (a) The total cotton production in Andhra Pradesh during the current cotton season has been estimated in the range of 16 to 17 lakh bales.

(b) Cotton Corporation of India has purchased 82,452 bales as on 9.3.93 from Andhra Pradesh State.

(c) The share of Andhra Pradesh in the total production of cotton and total purchases of cotton by the CCI in the country is as under:—

	In the Country	In Andhra Pradesh	%
Production (estimated) .	123.00	16.00	13
Purchases (as on 9-3-93) .	9.11	0.82	9

Raw meterial at subsidised rates to Handloom weavers

2434. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that handloom weavers get chemicals, dyes and other raw material used in the handloom industry at high cost;

(b) whether it is also a fact that Government proposed to provide these items to the weavers at subsidistd rates;

(c) if so, by when a final decisi is likely to be taken in this regai and

(d) if answer to part (b) above in negative what are the reas therefor?

THE MINISTER OF STATE THE MINISTRY OF TEXTII (SHRI G. VENKAT SWAMY): The prices of yarn, dyes and che cals used in the handloom indus have increased in the recent pas

(b) Government had already set up the National Handloom Development Corporation (NHDC) for making available yarn, dyes and other raw materials to handloom weavers at reasonble prices. A scheme for supply of hank yarn to handloom/weavers at mill-rate prices is also being implemented through NHDC. Under this scheme Government reimburses NHDC a subsidy @ 2 per cent of the value of yarn supplied towards cost of transportation and overheads.

(c) and (d) Do not arise.

सूती धागे का निर्यात

2435. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सूती धागे का निर्यात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में तथा किस मूल्य पर सूती धागे का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या सूती धागे का निर्यात करने से पूर्व सरकार द्वारा भारतीय बुनकरों के लिये इसकी उपलब्धता संबंधी मामले पर विचार किया जाता है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) सरकार सूती यार्न का निर्यात नहीं कर रही है । सरकार केवल अलग-अलग वर्ष के आधार पर सूती यार्न के निर्यात के लिये केवल मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करती है ।

(ख) पिछले तीन केलेंडर वर्षों के दौरान सूती यार्न के निर्यात की मात्रा तथा मूल्य नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	मात्रा मिलियन किग्रा० में	मूल्य मिलियन रु० में
1990	83.17	4757.99
1991	120.03	8540.03
1992	122.08	11043.62

(ग) सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा की घोषणा अपरिष्कृत कपास के उत्पादन तथा देशीय मांग तथा सूती यार्न का उत्पादन तथा कीमतों, विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र के लिए यार्न की जरूरतों आदि जैसे सभी संबद्ध संघटकों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद की जाती है ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात द्वारा थोक विक्रेताओं को छूट दिया जाना

2436. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम, गुजरात अपने थोक विक्रेताओं को छूट देता है;

(ख) यदि हां, तो किन नियमों के अधीन यह छूट दी जाती है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक थोक विक्रेता को कितने-कितने प्रतिशत की कितनी-कितनी राशि की छूट दी गई;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी छूट दिये जाने में होने वाले कदाचारों के संबंध में अपने स्तर पर कोई जांच करवाई है ; और